

प्रेषक,

सुभाष कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 12 फरवरी, 2009

विषय:- मै० परनामी रियल स्टेट प्रा० लि० को ग्राम बिन्दुखेड़ा तहसील किच्छा जिला ऊधमसिंहनगर में आवासीय कालोनी का निर्माण किये जाने हेतु कुल 2.108 है० भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-529/सात-स० भू० अ० / 2007 दिनांक-20.12.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै० परनामी रियल स्टेट प्रा० लि०, पंजीकृत कार्यालय ए० डी०-302-सी०, पीतमपुरा दिल्ली को ग्राम बिन्दुखेड़ा तहसील किच्छा जिला ऊधमसिंहनगर में आवासीय कालोनी का निर्माण किये जाने हेतु कुल 2.108 है० भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड, (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं यथा 306/1मि०, खसरा संख्या-306/2मि०, 306/3मि०, खसरा संख्या-187/13मि० एवं खसरा संख्या-187/14मि० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा। भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन (आवासीय कॉलोनी का निर्माण) के लिए करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है।

यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गयी भू कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों के लिये वैध होगी।

7- आवास विभाग के शासनादेश संख्या-1942/V/आ0-2006-115/2006 दिनांक-17.8.2006 एवं इसके क्रम में जारी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- महायोजना क्षेत्र में सम्मिलित न होने के कारण शासनादेश संख्या-459/V/आ0-2006-115 (आ)/2007 दिनांक-20.02.2007 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भू-उच्चीकरण शुल्क राजकोष में जमा किया जायेगा।

9- अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पेयजल विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग आदि की अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10- स्थल हेतु पहुँच मार्ग आदि निकटवर्ती क्षेत्र में प्रचलित महायोजना के अनुसार छोड़ा जायेगा।

11- भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों/विनियमों में भवनो की ऊँचाई, भू आच्छादन, एफ0ए0आर0, भू गेह पार्किंग सम्बन्धी मानकों में संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-2269/V/आ0-2007-55/आ0/2006 दिनांक-6.11.2007 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

12- प्रस्तावित स्थल विनियमित क्षेत्र में होने के कारण यदि उक्त भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन करना आवश्यक होगा तो संस्था द्वारा सक्षम एजेन्सी (अधीन आवास विभाग/राजस्व विभाग/अन्य सक्षम एजेन्सी) से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

13- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

16- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन न होने, भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०-390/समदिनांकित/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- 4- श्री मोहन लाल गुप्ता निदेशक मै० परनामी रियल स्टेट प्रा०लि० ए०डी०-302सी० पीतमपुरा दिल्ली।
- 5- ✓ निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 6- प्रभारी मीडिया केंद्र सचिवालय
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनु सचिव।